Naxalite Movement in Bihar, Jharkhand and Chattishgarh Since 2002

ABSTRACT

of the Ph.D. Thesis

Submitted to

JAMIA MILLIA ISLAMIA

for the award of the Degree of Doctor of Philosophy

Submitted By

AARFA RAJPUT

Under the supervision of

Prof. M. Muslim Khan

Department of Political Science

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES

JAMIA MILLIA ISLAMIA

NEW DELHI-110025

DECEMBER 2012

Naxalite Movement in Bihar, Jharkhand and Chattishgarh Since 2002

KEY WORDS: Naxalism, Operation Green hunt, Salwa Judum, Internal Security, Democracy, Displacement.

इस शोध का उद्देश्य **बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में वर्ष 2002 से आज तक** नक्सलवादी आंदोलन की समस्या, रूप–स्वरूप का अध्ययन करना है। बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में मौजूदा व्यवस्था/सरकार तथा माओवादियों के बीच एक सीधा द्वंद्वात्मक संघर्ष है। कोई पक्ष किसी को भी बर्दाशत करने को तैयार नहीं है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि व्यवस्था के रक्षक – हितग्राही तथा व्यवस्था के चरम विरोधी एक साथ रह नहीं सकते और यह घनघोर विरोधी ताकतें अगर एक ही समय में मौजूद हैं (और ऐसा है भी) तो वे कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रह सकतीं। अतएव दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नष्ट करने के लिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने माओवादी – नक्सलवादी हिंसा से निपटने के लिए अपनी अपनी रणनीतियाँ बनाकर लगातार इस समस्या से निपटने का प्रयास किया परंतु वर्ष 2004 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन और मुख्य नक्सलबाड़ी पार्टियों – धड़ों की एकता कायम होने के बाद इनकी ताकत एवं प्रभाव क्षेत्र में हुई एकाएक वृद्धि ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों को विवश किया कि वे पार्टीगत मतभेदों को भुलाकर एकजुट हों तथा एक ठोस रणनीति बनाकर नक्सलवाद–माओवाद से संयुक्त रूप से निपटें।

नक्सलवाद–माओवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों उड़ीसा, प. बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, आन्ध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने जहां आपस में तालमेल तेज किया वहीं इन राज्यों में सक्रिय राजनीतिक दलों कांग्रेस, बीजू जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, तेलगू देशम, झा.मु.मों., झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जनता दल (यू.), एन.सी.पी., शिवसेना ने भी किसी न किसी रूप में इस उद्देश्य हेतु अपनी सेवायें भी उपलब्ध कराने का वादा किया। विशेष उल्लेखनीय यह है कि इन राज्यों में कार्यरत अन्य कम्युनिस्ट पार्टियाँ – सी.पी.आई., सी.पी.आई. (एम.), एस.यू.सी.आई (सी.), आर.एस.पी. भी माओवादियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं और नक्सलबाड़ी आंदोलन से प्रेरणा लेने वाली तथा भा.क.पा. (माले.) से निकली हुई कम्युनिस्ट पार्टियाँ जिसमें भाकपा माले (लिबरेशन), भाकपा माले (रामचन्द्रन) आदि शामिल हैं भी माओवादियों के खिलाफ हैं और यह कम्युनिस्ट पार्टियाँ अब माओवादियों के 'भ्रातृ संघर्ष' में न होकर 'शत्रु संघर्ष' की कोटि में आ चुकी हैं। नक्सलवादी – माओवादी यह मानते हैं कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत में कायम राजसत्ता ने

'राष्ट्र–राज्य' के माध्यम से अपनी रणनीतियों का निरूपण किया है, सरकार और सरकार के अंग तो बाहरी मुखौटा हैं। दोनों पक्ष – राजसत्ता और उसके निर्देश पर चलने वाली सरकारें और नक्सलवादी – माओवादी आमने सामने डटे हैं। वे एक दूसरे को पराजित करने या ध्वस्त करने पर आमादा हैं। आज से लगभग 105 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि परस्पर विरोधी ताकतें कभी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करतीं – ''जब दो पक्ष आपस में संघर्षरत होते हैं तो सामान्यतया यह होता है कि वे दोनों अन्तिम समय तक एक अतिवादी स्थिति में रहते हैं। इन दोनों में जो पक्ष न्याय के पक्ष में होता है वह अपनी स्थिति में अंत तक दृढ़ रहता है जब तक कि वह विजयी न हो जाय।''[1] गांधी के यह विचार इन परिस्थितियों पर भी सीधे तौर पर लागू होते दिखते हैं। दोनों पक्ष अपने को न्याय के पक्ष में मानते हैं और अपनी अपनी स्थिति में दृढ़ हैं।

बिहार, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ बुनियादी कारण

आज गंभीर प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा बिहार के विभाजन के बाद से (2001–2002) नक्सलवाद–माओवाद के अभियानों में आई तेजी के बुनियादी कारण क्या है। इसके बुनियादी कारणों में – राजनीतिक दलों व संसदीय व्यवस्था के प्रति बढ़ती अनास्था, नक्सलवादी–माओवादी दलो गुटो के एकीकरण की प्रक्रिया में तेजी, आस–पास चल रहे सशस्त्र विद्रोहो से उर्जा अर्जित होना, बुद्धिजीवियों, लेखको, पत्रकारों का वैचारिक एवं नैतिक स्तर पर समर्थन, इन्टरनेट, फोन, टी.वी. के विस्तार से प्रचार–प्रसार का मौका मिलना, जन संघर्षो के निर्मम दमन से सशस्त्र संघर्ष की भूमि तैयार होना, प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य व कारपोरेट का बढ़ता कब्जा, आपरेशन ग्रीन हंट एवं सलवा जुडूम के दौरान निर्मम दमन, बेरोजगार युवा वर्ग का नक्सलियों की तरफ आर्थिक लाभ हेतु जाना आदि को रखा जा सकता है।

नक्सलवाद–माओवाद का एक वैचारिक आधार है जिसके प्रति सहमति या असहमति हो सकती है लेकिन बिना उनके वैचारिक आधार को चुनौती दिये हुए तथा इसको एक राजनैतिक परिघटना के रूप में स्वीकार करते हुए इस समस्या के बारे में एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक समाधान तक नहीं पहुँचा जा सकता। उसपर सवाल खड़े करते हुए ये कम्युनिस्ट पार्टीयां यह कहती है कि जन संगठनों, वर्ग संगठनों, संयुक्त मोर्चे के निर्माण की बुनियादी समझ के बगैर सीधे सशस्त्र संघर्ष छेड़ना एक गैर लेनिनवादी समझ है जो माओवादी विचारधारा के भी विपरीत है।

[1]Collected works of Mahtma Gandhi, Vol VII, p.146, Indian Opinion, date: 10-08-1907, The Publication Division, Govt. of India, July 1962